दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-१८० वा | शुक्रवार ३१ जनवरी २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

दिन दिए आधा, विकास का किये वादा, ''सिस्टम'' में बीड बिठा कर गए दादा।

दो सांसद, दो मंत्री, चार आमदार, सब खबरदार।

बीड़, ३० जनवरी (तामीर न्यूज -)

सूबह आठ बजे पालक मंत्री के साथ मीटिंग, अफसरान हो या लिडारांन सब के लिए बीड में नया अनुभव था उस में पालक मंत्री उपमुख्यमंत्री हो और अजीत दादा जैसा शिस्त प्रिय तो फिर सारी फिल्डिंग टाईट हो जाती है। आज भले हि बजट और विकास को लेकर बहुत कुछ न हुआ हो। लैकिन बारामती पैटर्न कि एक झलक सभी को देखने मिली, बीड जिला जो कुछ ज्यादा बदनाम हुआ या कर दिया गया उसे भी संभलने का मौका मिलेगा, साथ हि उपमुख्यमंत्री ने अपने पार्टी के लोगों को जो बातें बातों में जो डोस पिलाया उस से उन के भी समझ में आ गया होगा कि अब मन मानी नहीं चलेगी, अब कानून उन के जेब में नही रहेगा। साथ हि नियोजन कमेटी कि मिटिंग में माहूल को साफ करने कि जो बात उन्होंने कि वो गहेरा अर्थ रखती है।

इस मिटिंग में उन्होंने ने ये उपदेश दिया कि सभी प्रतिनिधि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर काम करें, तो बीड़ के बारे में बनी धारणा बदली जा सकती है। यह विचार राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं बीड़ के संपर्क मंत्री अजीत पवार ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यदि बीड़ की छवि बदलेगी, तो यहां निवेश आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

श्री अजीत पवार की अध्यक्षता में नियोजन सभागार में चालू वर्ष की योजना और अब तक हुए खर्च की समीक्षा की गई।

जिले की सामान्य योजना का बजट ४८४ करोड़ रुपये है, जबकि अनुसूचित उपयोजना का बजट १२९ करोड़ रुपये है। इसके साथ ही ओटीएसपी योजना के तहत २ करोड़ ५० लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल ६१५.५० करोड़ रुपये की नियत व्यय राशि स्वीकृत की गई है। सामान्य योजनाओं के अंतर्गत ४६७.७० करोड़ रुपये के कार्यो को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, और विभिन्न एजेंसियों को १२५.३९ करोड़ रुपये (कुल राशि का ४०%) वितरित किया गया है। इसमें से जनवरी के अंत तक १२३.३ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

कुल योजना में से ५३६.४४ करोड़ रुपये के कार्यो को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिनमें से १५६.४८ करोड़ रुपये वितरित किए गए और १५४.३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि:

इस बैठक में मंच पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सांसद रजनी पाटिल, सांसद बजरंग सोनवणे, बीड़ के संपर्क सचिव एवं आदिवासी विभाग के सचिव विजय वाघमारे, संभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिलाधिकारी अविनाश पाठक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवने, पुलिस अधीक्षक नवनित कावत, और सहायक जिलाधिकारी अर्पिता ठुबे उपस्थित थे।

इसके अलावा, योजना समिति के सदस्यों में विधायक सतीश चव्हाण, विक्रम काले, सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, नमिता मुंदड़ा, संदीप क्षीरसागर, और विजयसिंह पंडित शामिल थे।

बीड़ में निवेश लाने के लिए माहौल बदलने की आवश्यकता

बीड़ में निवेश आकर्षित करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। इसी दृष्टिकोण से कार्य करें। इसके लिए मुंबई से बीड़ तक सीधी रेलवे सेवा शुरू करने और भविष्य में बीड़ के लिए एक हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले का शेष बजट समीक्षा के बाद जारी किया जाएगा, इसलिए सभी अधिकारी अभी से काम में जुट जाएं। नगर पालिकाओं और सार्वजनिक निर्माण विभाग को सबसे पहले शहर की सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, अगली बार जब मैं दौरे पर आऊं, तो पूरा शहर स्वच्छ दिखना चाहिए।

बैठक से पहले विभागीय समीक्षा एवं निर्देश

बैठक से पहले, उपमुख्यमंत्री ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों से विभिन्न कार्यो की समीक्षा की और उन्हें बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काम में देरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत संविधान की प्रति भेंट कर किया गया। जिलाधिकारी अविनाश पाठक ने समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक की शुरुआत में 'निपुण भारत' अभियान के तहत 'पायाभूत साक्षरता संख्यान ज्ञान' विषयक पुस्तक का विमोचन किया गया।

शहीद दिवस पर मौन श्रद्धांजलि

आज, ३० जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर, ठीक ११:०० बजे, सभी उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

बैठक से जुड़े प्रमुख बिंदु:

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बीड़ संपर्क मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था। बैठक के लिए जिलाधिकारी कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

इस बैठक के अवसर पर, दो वर्षो के अंतराल के बाद, जिलाधिकारी कार्यालय की लिफ्ट फिर से चालू कर दी गई।

बैठक को लेकर सभी में उत्सुकता थी, जिसके चलते विभिन्न समाचार चैनलों के प्रतिनिधि सुबह से ही उपस्थित थे।

अगली बैठक से कम से कम १० दिन पहले सभी सदस्यों को बैठक का एजेंडा उपलब्ध कराने और इसकी पूर्व तैयारी हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, ताकि मुख्य बैठक का समय बचाया जा सके। बैठक में पूरी समीक्षा के बाद, उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सुझावों को संकलित कर मुंबई भेजा जाए।

सुरक्षित जल आपूर्ति, नाले के निर्माण सहित १७ डीपी सड़कों की समस्याओं का होगा समाधान

पटेल, नाईकवाड़े को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिया आश्वासन

बीड़, ३० (प्रतिनिधि): उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बीड़ शहर की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अमर नाईकवाड़े और फारूक पटेल ने एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि बीड़ शहर की जल आपूर्ति के लिए बकाया ४१ करोड़ ७५ लाख रुपये की राशि को विशेष मंजूरी देकर प्रदान किया जाए। साथ ही, शहर में जलना रोड के दोनों ओर के नाले और नगरोत्थान योजना के तहत १७ डीपी सड़कों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। इन तीन प्रमुख समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए, ऐसी मांग की गई। इस पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि बीड़ शहर के विकास से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला चौक से आनंदवाड़ी तक जाने वाला मुख्य मार्ग बीड़ शहर से होकर गुजरता है। यदि इस सड़क के दोनों ओर सीमेंट-कंक्रीट नाले का निर्माण किया जाता है, तो जलना रोड पर यातायात की समस्या दूर

हो जाएगी और बाजार क्षेत्र के व्यापारियों सहित शहरवासियों को राहत मिलेगी। इसके लिए ७ करोड़ रुपये की निधि मंजूर की जाए।

इसके अलावा, बीड़ की जल आपूर्ति करने वाले कादीवडगांव पंपिंग स्टेशन और ईट जल शुद्धीकरण केंद्र पर महावितरण (बिजली विभाग) का कुल बकाया ४१ करोड़ ७५ लाख रुपये है। इसे विशेष निधि के रूप में मंजूर किया जाए।

नगर परिषद बीड़ द्वारा शहर की १७ डीपी सड़कों का प्रोजेक्ट प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए ध्यान दें।

नगरसेवक अमर नाईकवाड़े और गुटनेता फारूक पटेल ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से अनुरोध किया कि इन तीनों प्रमुख समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। इस पर अजीत पवार ने आश्वस्त किया कि आपकी सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा।

हमेशा रहने वाली शिकायतों को खारिज किया गया

शिक्षा उप-संचालकों के लिए कोर्ट का आदेश; शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश

एम.टी. विशेष संवाददाता, नासिक

यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हुए शिक्षा अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करता है और यह शिकायत बार-बार की जाती है, तो अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसी आधार पर, मुंबई उच्च न्यायालय ने नासिक संभाग के शिक्षा उप-संचालक डॉ. भानुदास गीते और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी शिकायतों को गंभीरता से न लें।

डॉ. भानुदास गीते के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, और अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दिसंबर २०२३ में फैसला सुनाया कि इस तरह की बार-बार दोहराई जाने वाली शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह निर्णय उन कई शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राहत देने की उम्मीद है, जो अक्सर निराधार शिकायतों के कारण अनुचित दबाव का सामना करते हैं।

शिक्षा अधिकारी अक्सर कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर दायर की गई झूठी शिकायतों के कारण झूठे आरोपों का सामना करते हैं। ऐसे मामलों से प्रशासनिक स्तर पर गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अब, अदालत के इस निर्णय को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे निराधार आरोपों का शिकार न बनें।

उन्होंने किया तो प्रेम, हमने किया तो बलात्कार

राज ठाकरे का राजनीतिक दलों पर तंज

जमीर काज़ी, मुंबई:

वर्तमान राजनीतिक माहौल में सभी दलों की नीतियां बदलती रहती हैं, लेकिन भाजपा ने सबसे ज्यादा बार अपनी भूमिका बदली है। इसके बावजूद, ऐसा दिखाया जाता है कि हम अपनी भूमिका बदलते हैं। उन्होंने किया तो प्रेम, हमने किया तो बलात्कार, इसी अंदाज में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज राजनीतिक दलों पर जोरदार हमला बोला। वे वरली स्थित एनसीसीआई डोम सभागार में पार्टी पदाधिकारियों की सभा को संबोधित कर रहे थे।

चुनाव परिणाम और बदलती भूमिकाओं पर सवाल

राज ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित थे, और महाराष्ट्र की जनता अब तक उस झटके से उबर नहीं पाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि महज चार महीनों में लोगों की भूमिकाएं इतनी तेजी से कैसे बदल सकती हैं? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पार्टी में रहना है तो अनुशासन अनिवार्य होगा, और जल्द ही नई आचारसंहिता लागू की जाएगी।

भाजपा-शिवसेना के बदलते रिश्तों पर हमला

मनसे की भूमिका पर बार-बार सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बदलते संबंधों को उजागर किया। उन्होंने कहा:

१९६६ में शिवसेना ने पहली बार प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा।

बाद में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, फिर कांग्रेस को समर्थन दिया।

बाद में भाजपा के साथ गठबंधन किया।

उन्होंने कहा, हर बार परिस्थितियों के अनुसार दल निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं, तो हमें अलग नजर से देखा जाता है। उन्होंने किया तो प्रेम, हमने किया तो बलात्कार!

लोकसभा में मोदी को समर्थन देने की सफाई

राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में मोदी को समर्थन देने का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कई लोगों को लगता है कि मुझे भाजपा के नेताओं से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई चाय पीने बुलाए तो क्या कहें, घर पर ही पी लीजिए?

उन्होंने कहा, जब भाजपा के नेता मुझसे मिलने आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें समर्थन दे रहा हूं। न ही इसका मतलब यह है कि मेरा मराठी स्वाभिमान कमजोर हो गया है। मैं वही करूंगा जो महाराष्ट्र, मराठी लोगों और हिंदुओं के लिए सही होगा। आज नहीं तो कल, पर कल नहीं तो परसों, लेकिन जो करना है, वह जरूर किया जाएगा।

ईडी नोटिस और महायुति को समर्थन पर सफाई

राज ठाकरे ने कोहिनूर मिल मामले में ईडी नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन मुझे ईडी की नोटिस मिली, मैं खुद सोच में पड़ गया कि यह क्यों आई? उसमें कोहिनूर मिल का जिक्र था। लेकिन हमारा उस मामले से २००८ में ही कोई संबंध नहीं था। हमारे एक पार्टनर ने टैक्स नहीं भरा, इसलिए नोटिस निकाली गई।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि छह दिन पहले ७०,००० करोड़ रुपये के घोटाले की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम उन्हें जेल में डालेंगे। फिर अचानक अजीत पवार को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया।

राज ठाकरे ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अशोक चव्हाण और हेमंत बिस्वास को भी इसी तरह 'पावन' कर लिया।

भाजपा-शिवसेना गठबंधन का इतिहास

राज ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के संबंधों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा:

१९८० में भाजपा की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने और उन्होंने गांधीवादी समाजवाद की नीति अपनाई।

१९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के समय शिवसेना ने एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन था।

१९८६ में वाजपेयी भाजपा के अध्यक्ष थे, पार्ले में चुनाव हुए, और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा ने जीत हासिल की।

१९८४ में भाजपा-शिवसेना गठबंधन हुआ, उस समय शिवसेना के दो उम्मीदवार भाजपा के कमल चिन्ह पर लड़े थे।

आज की महाराष्ट्र सरकार में ज्यादातर लोग शिवसेना और कांग्रेस से आए हुए हैं।

महायुति को समर्थन का कारण

उन्होंने कहा कि २०२४ के लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने का निर्णय पूरी परिस्थिति को देखकर लिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महायुति को समर्थन देने का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक हालात को ध्यान में रखकर किया गया निर्णय है।

आ. संदीप क्षीरसागर ने डीपीडीसी बैठक में महत्वपूर्ण लोकप्रश्न उठाए

विकास कार्यो के लिए विशेष अतिरिक्त निधि की मांग

बीड, ३० जनवरी (प्रतिनिधि):

राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं बीड के संपर्क मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई जिला नियोजन समिति (डीपीडीसी) की बैठक में आ. संदीप क्षीरसागर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। साथ ही, क्षेत्र के विकास के लिए विशेष अतिरिक्त निधि की मांग की।

प्रमुख मांगें:

बीड पंचायत समिति परिसर में स्व. अण्णासाहेब पाटील व स्व. विनायकरावजी मेटे की प्रतिमा स्थापित करना।

३० बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल बीड में निर्माण हेतु सरकारी जमीन आवंटित करना।

नगर परिषद की ३६ करोड़ रुपये की महावितरण बकाया राशि का भुगतान, जिसे उपमुख्यमंत्री ने मंजूरी दी।

बीड शहर में बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।

अल्पसंख्यक लड़कियों के छात्रावास के लिए सरकारी परिसर में भूमि उपलब्ध कराना।

बीड नगर परिषद को १० करोड़ रुपये की निधि नवाचार योजना के तहत मंजूर करना।

पुराने तहसील कार्यालय की जमीन नगर परिषद को हस्तांतरित कर वहां उर्दू भवन और दुकानों का निर्माण करना।

२०२० की लंबित फसल बीमा राशि जल्द से जल्द किसानों के खातों में जमा कराना। महाडीबीटी योजना के लाभार्थियों को अनुदान जारी करना, जो अब तक नहीं मिला है।

श्री क्षेत्र कपिलधार के लिए १०० करोड़ रुपये के विकास आराखड़ा को मंजूरी देना।

शिवणी स्थित महाविहार धम्मभूमि को क' श्रेणी तीर्थस्थल का दर्जा देना।

खंडेश्वरी मंदिर खेल संकुल के लिए ५ करोड़ रुपये की निधि को पूरी तरह जारी करना।

बीड जिला खेल संकुल के जीर्णोद्धार के लिए १७ करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान करना।

बीड जिले में बिजली आपूर्ति को सुधारने के लिए नए उपकेंद्र स्थापित करना।

बीड व शिरूर कासार तालुका में स्कूल भवन, मरम्मत और कंपाउंड वॉल के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

रेलवे ब्रिज की मांग - शिरूर तालुका के हिवरसिंगा, जवळागिरी, और बरगवाडी गांवों में यातायात की समस्याओं के समाधान हेतु रेलवे विभाग से समन्वय करना।

संक्षेप में:आ. संदीप क्षीरसागर ने बीड जिले के विकास, शिक्षा, आधारभूत संरचना, बिजली, कृषि, और खेल सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और इनके लिए सरकार से वित्तीय सहायता और नीतिगत निर्णय लेने की मांग की।

संतोष देशमुख और सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेंगे: सुप्रिया सुले

मुंबई, ३० जनवरी (अज़ीज़ एजाज़):

एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि महाराष्ट्र में वसूली, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ वे पूरी ताकत से लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी-एसपी के सभी सांसद इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और बजट सत्र में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और वसूली जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। वे आज पुणे में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं।

संतोष देशमुख हत्या मामले में सरकार पर सवाल

सुप्रिया सुले ने मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी कृष्णा आंधले पिछले ५१ दिनों से फरार है, लेकिन सरकार उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उपमुख्यमंत्री को दस्तावेजी सबूत सौंपे हैं, जिन पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है।

फसल बीमा घोटाला और हार्वेस्टर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप

सुप्रिया सुले ने कहा कि बीड़ जिले में फसल बीमा घोटाला और बारामती लोकसभा क्षेत्र में हार्वेस्टर योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने खुद इस भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है, और यह घोटाला पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ था। सरकार के पास इस घोटाले की पूरी जानकारी है, इसलिए इसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए।

विधायक को इस्तीफा देने की सलाह

उन्होंने कहा कि विधायक सुरेश धस ने बोगस बिलों को लेकर खुलासा किया है, इसलिए उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

मुख्यमंत्री के फैसले पर नजर

सुप्रिया सुले ने कहा कि अंजलि दमानिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुणे के प्रभारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री ने फैसला लेने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दी है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं।

संतोष और सोमनाथ को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा

उन्होंने कहा कि बीड़ में होने वाली डीपीडीसी (जिला नियोजन समिति) की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बीड़ के सांसद बजरंग सोनवणे ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक बीड़ और परभणी के सोमनाथ और संतोष को न्याय नहीं मिलता, वे शांत नहीं बैठेंगी।

पानी के बिलों में बढ़ोतरी का विरोध

सुप्रिया सुले ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह पानी के टैक्स में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं देंगी, और अगर सरकार ने पानी के बिलों में इजाफा किया तो वह कड़ा विरोध करेंगी।

गरीब मरीजों के लिए बजट क्यों नहीं? उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास मेट्रो और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए करोड़ों रुपये हैं, तो गरीब और मेहनतकश मरीजों की सेहत पर खर्च करने में क्या दिक्कत है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे, तो इन बुनियादी सुविधाओं का क्या फायदा?

मनोज जरांगे का अनशन स्थगित, न्याय के लिए मुंबई जाने की चेतावनी

जालना, ३० (प्रतिनिधि): देवेंद्र फडणवीस मराठा समाज के साथ १००% गद्दारी नहीं करेंगे। वे हमारी मांगें स्वीकार करेंगे, और अगर नहीं कीं, तो हम जल्द ही मुंबई आने की तारीख घोषित करेंगे। उस समय मुंबई पूरी तरह जाम हो सकती है। मराठा पीछे नहीं हट सकते। हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे युवा भड़क गए, तो वे विधायकों और सांसदों को निशाना बना सकते हैं। मराठा समाज एक बार जो निर्णय लेता है, उसे वापस नहीं लेता।

इस तरह की चेतावनी देते हुए मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील ने अपना अनशन स्थगित कर दिया। इस फैसले में विधायक सुरेश धस, सांसद बजरंग सोनवणे और विधायक संदीप क्षीरसागर आदि ने मध्यस्थता की।

अब अनशन नहीं, सीधी लड़ाई होगी

मनोज जरांगे पाटील ने कहा, पिछले करीब सवा दो साल से मैं यह सब सहन कर रहा हूं। आज हम अनशन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अब संभवतः फिर अनशन नहीं होगा, बल्कि अब आमने-सामने की लड़ाई होगी। मैंने देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने ८ मांगें रखी थीं, क्या वे पूरी की जाएंगी या नहीं? मैंने अब तक फडणवीस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर मराठा समाज की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो मैं सरकार को चैन से नहीं रहने दूंगा।

उन्होंने आगे कहा, अगर आप हमारी मांगें पूरी करेंगे, तो समाज आपको सर पर उठाएगा, लेकिन अगर नहीं किया, तो मैं मुंबई जाने की तारीख घोषित करूंगा। गरीब मराठाओं को न्याय मिलना चाहिए।

सरकार की वादाखिलाफी पर नाराजगी

मनोज जरांगे पाटील ने कहा कि वे पिछले ६ दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। मराठा समाज के लिए सामूहिक अनशन किया गया। उन्होंने कहा, **हमें लगा था कि इतने दिन अनशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री लगातार वादाखिलाफी कर रहे हैं। सरकार सिर्फ समय निकाल रही है। कुणबी प्रमाणपत्र की जांच करने वाली समिति को

महाराष्ट्र गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए आयोग तैयार

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई: आगामी २ फरवरी को आयोजित होने वाली महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पूरी तरह तैयार है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। यह अपील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की सचिव, डॉ. सुवर्णा खरात ने की।

नवी मुंबई के बेलापूर स्थित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि २ फरवरी को होने वाली महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४' के संबंध में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो कि पूरी तरह गलत है।* सभी प्रश्नपत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षित रखे गए हैं और इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।*

उन्होंने बताया कि कुछ मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का लालच देकर पैसे मांगे जाने की शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने पुणे पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। आयोग और पुणे पुलिस मिलकर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

अगर किसी अभ्यर्थी को इस तरह के फोन कॉल आते हैं, तो वे लेपींरलीं- ीशलीशींरीूीिलि.सेीं.ळप पर ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ पूरे राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल २,८६,००० अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com